Almost all the States in the country have been covered in this expansion project. In the second phase, we are going to expand a few more projects. After the CCA gives its approval, I will be able to inform you about them.

कपास उत्पादकों की आय

*164. **श्री राम जेठमलानी:**

श्री शिवानन्द तिवारी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और विश्व के पांच प्रमुख कपास उत्पादक देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन देशों में कपास उत्पादकों को कपास उत्पादन से प्रति हैक्टेयर कितनी आय होती है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में से एक है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के 2007 के अनुमानों के अनुसार, भारत का विश्व में सबसे अधिक कपास उगाने में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। अन्य अधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान तथा ब्राजील हैं। निम्न सारणी इन देशों में कपास के उत्पादन तथा कपास उत्पादकों की प्रति हैक्टेयर निवल आय को दर्शाती है :

देश	उत्पादन (मिलियन टन)	शुद्ध आय (अमरीकन डॉलर/हेक्टेयर)
चीन	8.078	788*
भारत	5.355	159
यू.एस.ए.	4.182	131
पाकिस्तान	1.845	251
ब्राजील	1.603	498

स्रोत: एफ.ए.ओ.

नोट: निवल आय में स्थिर मूल्य शामिल नहीं हैं

* चीन के संदर्भ में श्रम मूल्य शामिल है

Income of cotton producers

*164.SHRI RAM JETHMALANI: †

SHRI SHIVANAND TIWARI: ††

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is one of the leading cotton producing countries in the world;

(b) if so, the facts in this regard and the names of five leading cotton producing countries of the world; and

(c) per hectare income of cotton producers from cotton production in these countries?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi

†The question was actually asked on the floor of the House by (Shri Shivanand Tiwari)

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. India is one of the leading cotton producing countries in the world. As per the Food and Agriculture Organization (FAO) estimates for 2007, India is the second largest producer of Cotton in the world after China. The other three leading producers are United States of America, Pakistan and Brazil. Table below presents the production of cotton and per hectare net income of cotton producers in these countries:

Country	Production (Million Tonnes)	Net Income (US$/Hectare)
China	8.078	788*
India	5.355	159
USA	4.182	131
Pakistan	1.845	251
Brazil	1.603	498

Source: FAO

Note: Net income does not include fixed costs.

* In case of China, net income includes labour cost also.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, सरकार की और से जवाब आया है, उसमें कपास का जो प्रति हैक्टेयर उत्पादन है, उसमें जो प्रति हैक्टेयर शुद्ध आमदनी है, शुद्ध मुनाफा है, वह चार्ट में बताया गया है कि चीन में 788 डालर प्रति हैक्टेयर आमदनी है, भारत में वही आमदनी 159 डालर प्रति हैक्टेयर है, पाकिस्तान में 251 डालर है और ब्राज़ील में 498 डालर है। यह इतना बड़ा फर्क है, जब कि चीन के बारे में कहा जा रहा है कि 788 डालर प्रति हैक्टेयर जो आमदनी है, उसमें लेबर कॉस्ट भी शामिल है। जो यह इतना बड़ा गैप है, इसका क्या कारण है? हमें जो एक कारण समझ में आता है कि प्रति हैक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, वह उनके यहां काफी ज्यादा है, हमारे यहां कम है। अगर आमदनी के फर्क का यही कारण है, तो प्रति हैक्टेयर प्रोडेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इस बारे में जानना चाहेंगे?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, there are a number of reasons why our production in cotton is less as compared to other countries. Firstly, about 66 per cent of cotton growing area in our country is rainfed. There is no assured water. Secondly, our cotton crop is prone to pests and diseases. Thirdly, there is excessive use of pesticides, which has developed a resistance in insects against the pesticides. Another important reason is the large-scale use of lint seed by the farmers because of poor plan, which, ultimately, affects the total yield. Of course, price was also one of the important issues which has been corrected recently, but the main reason is that a substantial area for growing cotton in our country in rainfed. There is no assured water. That is one of the reasons why our production in cotton is less as compared to other countries. There are a number of schemes which have been implemented in the last three years. मुझे एक ही बात बतानी है कि इसका असर हो रहा है। हमारे देश में जो प्रति हैक्टेयर यील्ड आता है, 2002-03 से या इससे पहले अलग-अलग किस्म के Missions, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, इस पर ध्यान दिया गया था। ये जो Mini Missions - I, II, III and IV हैं, जिन पर कॉटन एरिया में अमल किया गया, इससे प्रति हेक्टेयर यील्ड में एक तरह से सुधार हो रहा है और वह सुधार हम लोगों को दिख रहा है। सन् 2002-03 में प्रति हेक्टेयर यील्ड 191 किलोग्राम था, वह 2003-04 में 307 हो गया, 2004-05 में 318 हो गया, 2005-06 में 362 हो गया, 2006-07 में 421 हो गया, 2007-08 में 468 हो गया और इस साल हम expect करते हैं कि 468 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। That means, in six years, from 191 we have come to 461. So, this is a clear-cut indication that our per-hectare yield is, definitely, improving, but,

still that is not satisfactory. There are major five countries which produce cotton in the world and our position is fourth. We are just above America. Otherwise, other countries have a definitely better performance than us. The major reason is that their most of the cotton growing areas are under assured water.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे यहां उत्पादन में कमी का मुख्य कारण है रेनफेड पर, बरसात के पानी पर हमारे कॉटन के उत्पादन का निर्भर होना। यह सिर्फ कॉटन का ही मामला नहीं है, हमारी पूरी खेती का यह संकट है कि अधिकांश जगह हम बरसात के पानी पर, प्रकृति के पानी पर ही निर्भर करते हैं। यह तो उसकी मूल समस्या है। हमारा यह कहना है कि कॉटन का जो genetically modified seed है, जिसके बारे में यह दावेदारी रही है कि किसान इसका इस्तेमाल करेंगे, तो productivity में बहुत बड़ा फर्क आएगा, इन्होंने जैसा बताया है, निश्चित रूप से थोड़ा फर्क आया है, लेकिन जब हम चीन के साथ, ब्राजील के साथ, यहां तक कि बगल में पाकिस्तान के साथ तुलना करते हैं, तो उसके मुकाबले हमारे किसानों की जो प्रति हेक्टेयर आमदनी है, वह काफी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या उसके बारे में सरकार के पास कोई concrete योजना है, वह हम जानना चाहेंगे?

श्री शरद पवार: महोदय, मैंने कहा कि इस देश में पिछले 6-7 सालों में चार Mini Missions अमल किए गए हैं, Mini Missions Nos. I, II, III, and IV और इसका असर हमें फील्ड में दिख रहा है। जब तक हम ठीक तरह से पानी का बन्दोबस्त नहीं करेंगे, तब तक यह उत्पादन जिस तरह से चीन जैसे देशों में मिलता है, उतना अपने देश में नहीं मिलेगा। यह बात सच है कि समूची खेती के बारे में यह समस्या है। आज हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत जमीन under irrigation है। देश की अनाज की जो जरूरत है, इसमें से 60 प्रतिशत अनाज यह 40 प्रतिशत irrigated जमीन पैदा करती है और बाकी जो 60 प्रतिशत जमीन है, जो rain-fed है, उसमें 40 प्रतिशत अनाज पैदा होता है। इसलिए जब तक हम हर स्टेट में irrigation के प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा-से-ज्यादा लागत नहीं लगाएंगे, तब तक इसका overall असर हमारे उत्पादन पर नहीं होगा। आज इसका असर हो रहा है। कॉटन के बारे में परिवर्तन हो रहा है कि कॉटन में जो बीटी कॉटन की नई variety आई, इसका क्षेत्र अपने देश में बढ़ रहा है और उत्पादन बढ़ने से इसका असर हमें अच्छी तरह से दिख रहा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Injectible polio vaccine

*165. DR. JANARDHAN WAGHMARE:

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government plans to introduce an injectible form of polio vaccine (IPVO), along with the oral dosage, in selected districts of U.P. and Bihar to wipe out the virulent strain of polio virus;

(b) if so, the facts and details thereof;

(c) whether some of the foreign based foundations have agreed to provide funds to the Union Government for this purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) and (b) India Expert Advisory Group in its meeting held on 10-11 November, 2008, has recommended that plans should be developed for the delivery of a supplementary dose of injectible Polio Vaccine in the highest risk districts of western Uttar Pradesh.

(c) and (d) No proposal has been received in this regard so far.